[श्री दौलत राम सारण]

का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। आजकल ऐसे 18 सैनिक स्कूल हैं। प्रधानाचार्य, रजिस्ट्रार, प्रधानाध्यापक तो रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा-सेनाओं के सक्रिय सेवा के सदस्य होते हैं, बाकी स्टाफ राज्य सरकार से अपना वेतन पाता है। इस प्रकार ये विद्यालय दोहरी शासन व्यवस्था से त्रस्त हैं। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की बढ़ाई गई रकम छात्रों को न केन्द्रीय सरकार देती है और न राज्य सरकार।

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक सैनिक स्कूल है। शिक्षा भवन एवं छात्रावास बहुत पुराने हैं लेकिन उसकी रख रखाव अच्छी न होने के कारण इनकी हालत जीर्ण शीर्ण है। यहां के शैक्षणिक स्टाफ को सेवा निवृत्त पर पैंशन व ग्रेचुइटी आदि का लाभ नहीं मिलता है और न योग्यतानुसार वेतन ही मिलता है। इससे निरंतर इन संस्थाओं के शिक्षा स्तर में गिरावट हो रही है। अशैक्षणिक स्टाफ भी कुव्यवस्था का शिकार है।

छात्रों पर प्रतिदिन जो व्यय किया जाता है, वह बहुत ही कम है। उपयुक्त भोजन व्यवस्था के अभाव में छात्रों में बीमारियां फैल रही हैं। स्कूल में छात्रों के स्वास्थ्य एवं बीमारी को देखने के लिए चिकित्सक की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इन समस्त सैनिक स्कूलों सहित चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल की आर्थिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी वहन करे, विद्यालय की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर में गिरावट को रोकें और प्रतिभावान छात्रों के नैतिक स्तर एवं मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए अन्य सम्यक कदम उठाएं।

(vi) Need to start 'auction sale' of tobacco through Tobacco Board for stabilisation of tobacco prices

PROF. N. G. RANGA (Guntur : Tobacco growers, especially the producers of Virginia tobacco, when in Andhra, Karnataka and Gujarat had to be assisted on two occasions by the Central Government through large scale purchases made by the state Trading Corporation, i e. in 1977-78 and 1982-83. What with the non-availability of adequate trained staff and adhoc crash arrangements which had to be made by STC at the stage of purchase of tobacco and also during the grading and storing of the purchased tobacco, the STC sustained heavy losses and growers failed to gain adequate protection and satisfaction. So Government appointed a Working Group to consider and suggest steps to be taken by Government to bring better stability in the tobacco market, ensure a fair and remunerative price to the tobacco growers and maximise export earning This working group has suggested that a crash programme should be undertaken by Government, through the statutorily established Tobacco Board to introduce auction system to cover all the tobacco growing areas in Andhra Pradesh to start with. The Working Group has therefore recommended that the Tobacco Board should go ahead gearing itself for the introduction of the permanent infrastructure and in the meanwhile, Tobacco Board should conduct test auctions in Andhra Pradesh in 1984. I suggest that Government should allot at least Rs. 3 crores to enable the Board to make all the needed arrangements to face the challenge of the 1984 crop season.

(vii) Need to ban import of rayon thread

श्री जगन्नाथ पाटिल (ठाणे) : महाराष्ट्र के थाने जिले में रेयान के धागे बनाने वाली दो कम्पनियां (1) नेशनल रेयान कोरपो-